

भारत के आर्थिक संवृद्धि मॉडल पर पुनर्विचार

यह एडिटरियल 14/02/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "[Why India needs deep industrialisation](#)" लेख पर आधारित है। इसमें भारत की आर्थिक चुनौतियों से निपटने और उसके विकास पथ को बनाए रखने के लिये गहन औद्योगिकरण के महत्त्व के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

[औद्योगिक उत्पादन सूचकांक \(IIP\)](#), [MSME क्षेत्र](#), [उत्पादन-लकड़ प्रोत्साहन \(PLI\)](#), [पीएम गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान](#), [स्टार्ट-अप इंडिया](#), [PPP मॉडल](#), [उद्योग 4.0](#), [सेवा क्षेत्र](#), [वनिर्माण क्षेत्र](#)।

मेन्स के लिये:

भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ, औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु हाल की सरकारी पहल।

[कोविड-19 महामारी](#) ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को नया आकार प्रदान किया है, जहाँ वैश्वीकरण से पीछे हटने की स्थिति बनी है। विश्व के देश अब गहन औद्योगिकरण नीतियों और राज्य नेतृत्व वाले आर्थिक हस्तक्षेपों को अपना रहे हैं। अमेरिका के मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम (Inflation Reduction Act), [यूरोपियन ग्रीन डील \(European Green Deal\)](#) और [भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल](#) को इसके उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है।

इस परिदृश्य में, भारत द्वारा भी ऐसी नीतियाँ अपनाये जाने की उम्मीद है जो वनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के तीव्र विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हों, ताकि जनसांख्यिकी और [औद्योगिक क्रांति 4.0](#) के लाभों का लाभ उठाया जा सके।

औद्योगिकरण बनाम गहन औद्योगिकरण :

- गहन औद्योगिकरण (Deep Industrialisation) अपने फोकस और दायरे में पारंपरिक औद्योगिकरण से भिन्न है।
- जबकि औद्योगिकरण आमतौर पर किसी क्षेत्र या देश में उद्योगों के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, गहन औद्योगिकरण संवहनीय एवं समावेशी विकास पर बल देते हुए आगे बढ़ता है।
 - इसमें उद्योगों को उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना शामिल है।
 - गहन औद्योगिकरण का लक्ष्य केवल तीव्र औद्योगिक वसति के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण है।

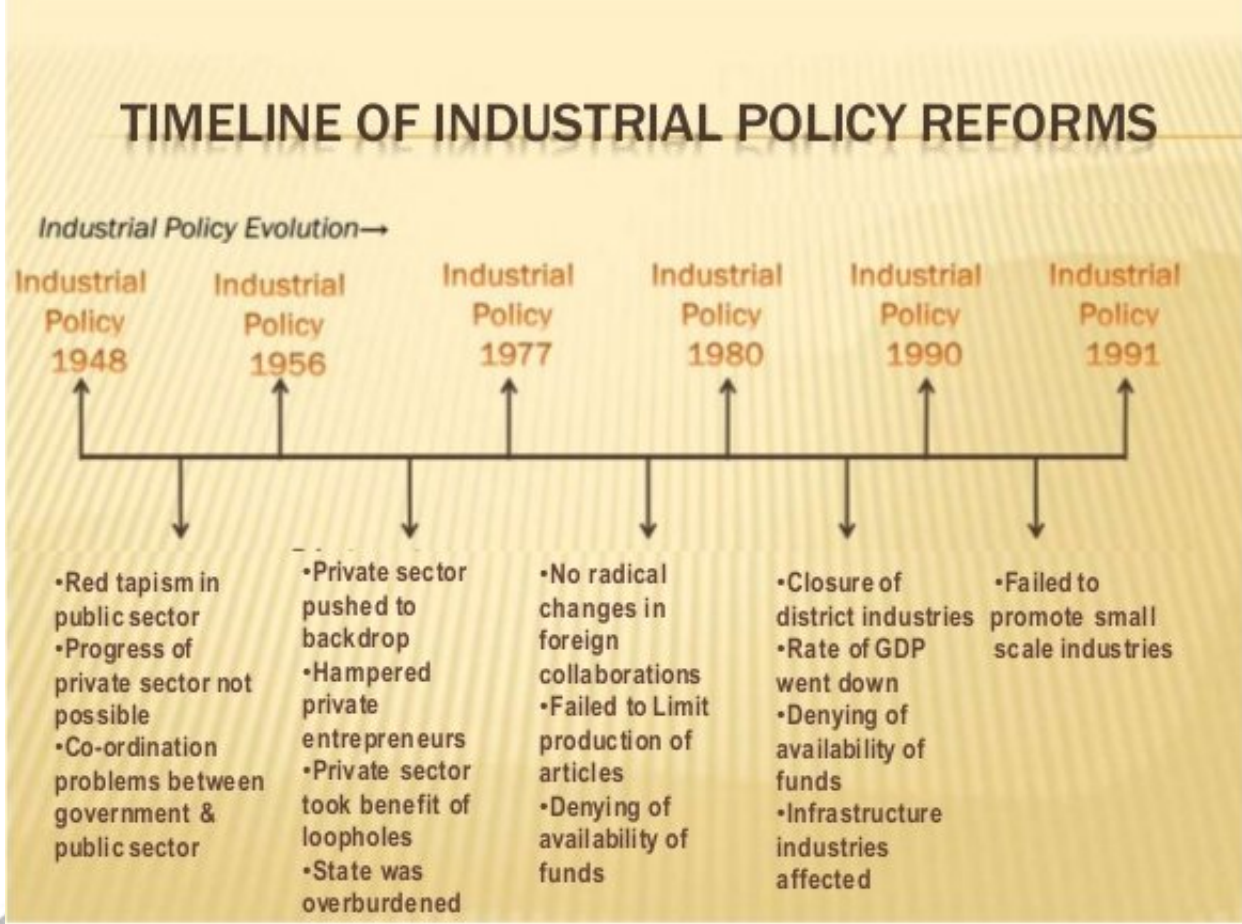
भारत में गहन औद्योगिकरण की आवश्यकता क्यों है ?

- **अप्रभावी वनिर्माण प्रतिसिपर्द्धात्मकता:**
 - वनिर्माण क्षेत्र में प्रतिसिपर्द्धात्मकता में सुधार के लिये हाई-टेक अवसंरचना और कुशल जनशक्ति बेहद महत्त्वपूर्ण है। लेकिन भारत को प्रमुख शहरों के बाहर सीमांत [दूरसंचार सुविधाओं](#) और घाटे में चल रहे राज्य बज्जिली बोर्डों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 - भारत में औद्योगिक नीतियाँ वनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने में विफल रही हैं, जिसका [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) में योगदान वर्ष 1991 से लगभग 16% के स्तर पर गतिहीन बना हुआ है।
- **पर्याप्त परिवहन सुविधाओं का अभाव:**
 - अतिभारक रेल नेटवर्क और विभिन्न समस्याओं से घरेलू सड़क परिवहन के साथ भारत की परिवहन अवसंरचना दबाव में है। ये चुनौतियाँ माल की कुशल आवाजाही में बाधा डालती हैं और वनिर्माण प्रतिसिपर्द्धात्मकता को प्रभावित करती हैं।
- **MSME क्षेत्र की बाधाएँ:**
 - मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में [MSME क्षेत्र](#) को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। MSME क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिये इस पूर्वाग्रह में सुधार की आवश्यकता है, जो भारत के आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **आयात पर उच्च निर्भरता:**
 - भारत अभी भी परिवहन उपकरण, मशीनरी, लौह एवं इस्पात, रसायन एवं उर्वरक सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये विदेशी आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता आयात प्रतिसिर्थापन रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

- भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का कुल औद्योगिक उत्पादन 38% योगदान देता है। सगिापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे नव-औद्योगिक देशों में यह प्रतिशत क्रमशः 52%, 29% और 28% है।

■ प्रभावी औद्योगिक नीति सुधारों का अभाव:

- ऐतिहासिक रूप से, औद्योगिक स्थानों को प्रायः लागत-प्रभावशीलता के बजाय राजनीतिक कारणों से चुना गया। इसके अतिरिक्त, आरंभिक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने से लालफीताशाही एवं श्रम-प्रबंधन संबंधी मुद्दों के कारण अक्षमता एवं हानि की स्थिति बनी, जिससे उन्हें बनाए रखने के लिये महत्वपूर्ण सरकारी व्यय की आवश्यकता हुई।



■ नविश का चयनात्मक प्रवाह:

- उदारीकरण के बाद नविश के वर्तमान चरण में, जबकि कुछ उद्योगों में पर्याप्त नविश आ रहा है, कई बुनियादी एवं रणनीतिक उद्योगों— जैसे इंजीनियरिंग, बजिली, मशीन टूल्स आदि में नविश की धीमी गति चिंता का विषय है।

■ विभिन्न उपभोग-प्रेरित विकास:

- व्यापार नीति सुधार पर अधिक बल दिये बिना आंतरिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप 'नविश' या 'नरियात-प्रेरित विकास' के बजाय 'उपभोग-आधारित विकास' की राह खुली।

भारत के औद्योगिकरण से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

■ महामारी के बाद भारत का विकृत आर्थिक परिदृश्य:

- भारत ने महामारी से अपेक्षाकृत तेज़ी से उबरते हुए अपनी विकास गति को बनाए रखा है। हालाँकि यह 'समय-पूर्व व औद्योगिकरण' (premature deindustrialization) का अनुभव कर रहा है, जहाँ उच्च विकास से एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग को लाभ होता है, जिससे मौजूदा असमानताएँ बढ़ जाती हैं।

- जहाँ महंगी कारें धड़ाधड़ बिक रही हैं, वहीं आम लोग उच्च खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं, जो भारत के विकास मॉडल में संरचनात्मक खामियों को उजागर करता है।

■ सेवा-आधारित विकास की कमियाँ:

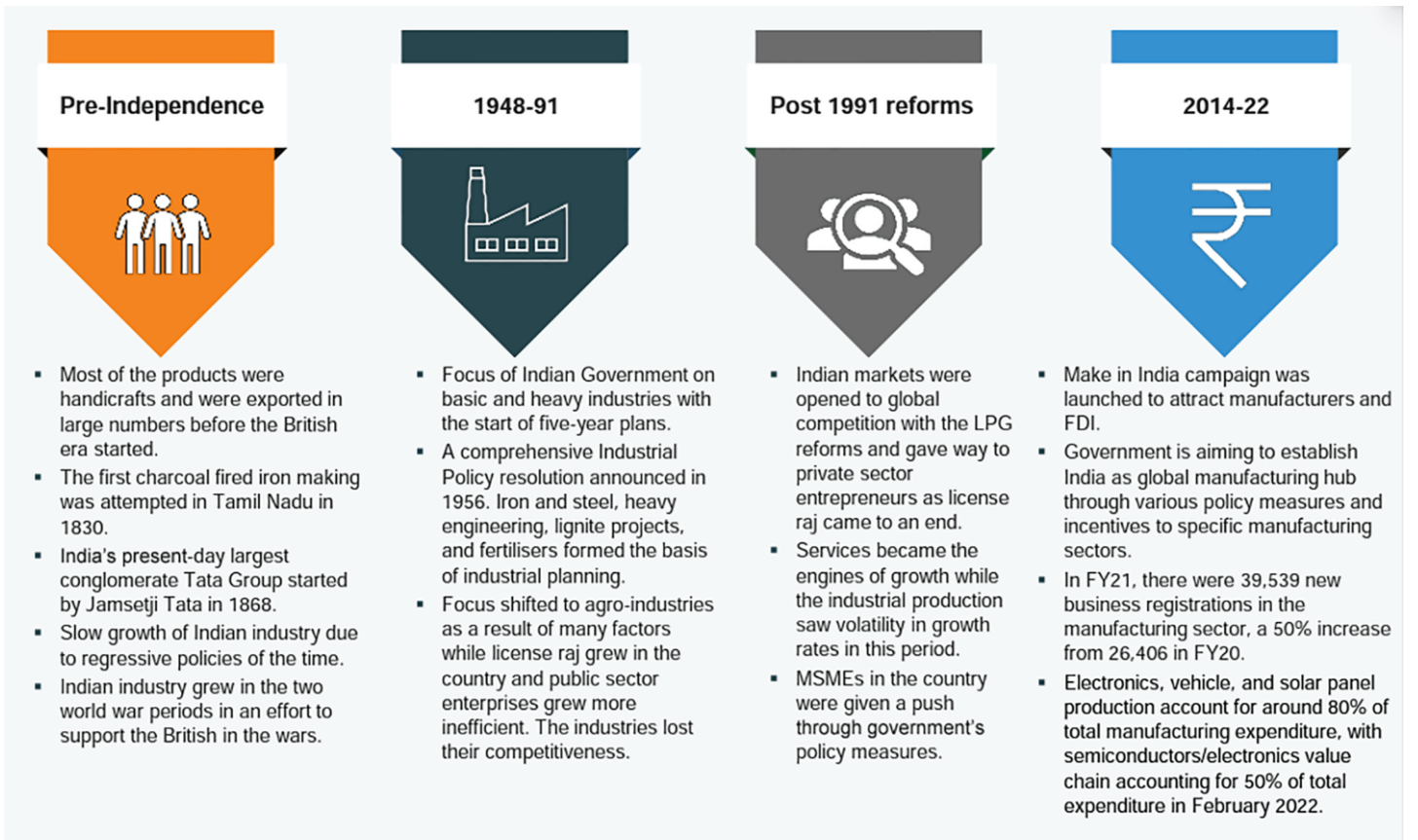
- हालाँकि 1980 के दशक के उत्तरार्ध से सेवा-संचालित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन इसने कृषि से श्रम को उतने प्रभावी ढंग से अवशोषित नहीं किया है जितना कि विनिरमाण ने किया।
- इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र को अत्यधिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है, जिससे गहरी असमानताएँ पैदा होती हैं। उच्च शिक्षा में नविश ने बुनियादी एवं प्रारंभिक शिक्षा की अपेक्षा में योगदान किया है, जिससे असमानताएँ और बढ़ गई हैं।

■ शैक्षिक असमानताएँ और औद्योगिक गतिहीनता:

- भारत की शिक्षा प्रणाली गहरी असमानताओं को परिलक्षित करती है, जहाँ मानव पूंजी में नविश अभिजात वर्ग के पक्ष में झुका हुआ है। इसके कारण बड़े पैमाने पर उद्यमशील उद्यमों का अभाव है जो चीन से उलट स्थिति है।

- स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की भिन्न गुणवत्ता असमान श्रम बाज़ार परिणामों में योगदान करती है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के पहली पीढ़ी के स्नातकों को प्रभावित करती है।
- **औद्योगीकरण में सांस्कृतिक कारक:**
 - औद्योगीकरण के लिये एक प्रमुख सांस्कृतिक शर्त है जन शिक्षा, जिसका भारत में अभाव है। जोएल मोकरि (Joel Mokyr) का मानना है कि तकनीकी प्रगति एवं विकास के लिये उपयोगी ज्ञान का उदय महत्त्वपूर्ण है।
 - भारत में वनिरिमाण के लिये आवश्यक कुछ व्यवसायों का सांस्कृतिक अवमूल्यन, साथ ही व्यावसायिक कौशल का अवमूल्यन, जैविक नवाचार और औद्योगिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।
- **रोज़गार सृजन में चुनौतियाँ:**
 - भारत का श्रम बाज़ार नमिन वेतन वाली और अनौपचारिक नौकरियों से चहिनति होता है। अधिकांश MSMEs असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनमें रोज़गार सृजन के लिये लचीलेपन का अभाव है। चीन का अनुभव रोज़गार सृजन के लिये वनिरिमाण क्षेत्र में 'स्केल' या पैमाने के महत्त्व को रेखांकित करता है।
 - भारत के 63 मिलियन MSMEs में से 99% से अधिक असंगठित क्षेत्र में हैं जिनमें उत्पादक रोज़गार सृजन के लिये बहुत कम लचीलापन है। उनका नरिवाह अस्तित्व नौकरियों या पैमाने के लिये कोई नुस्खा नहीं है। चीन का उदाहरण अधिक से अधिक नौकरियों के लिये वनिरिमाण में पैमाने के प्रभाव का सुझाव देता है।
 - नयिमति एवं व्यापक डेटा के अभाव में **मेक-इन-इंडिया (MII)** के प्रभाव का आकलन करना चुनौतीपूर्ण है। जबकि **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI)** उच्च-स्तरीय वनिरिमाण को लाभ पहुँचाती है, पारंपरिक वनिरिमाण क्षेत्र आम लोगों के मध्य रोज़गार सृजन के लिये महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।
- **संरक्षणवाद की चिंताएँ और अतीत के अनुभव:**
 - 1970 और 1980 के दशक में संरक्षणवाद के पछिले अनुभवों ने कमी और रेंट-सीकगि (rent-seeking) व्यवहार का रास्ता खोला, जिससे उपभोक्ताओं की तुलना में उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। ऐसी आशंकाएँ हैं कि MII के तहत संरक्षणवादी उपायों के सदृश परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
 - वर्ष 2011 की **राष्ट्रीय वनिरिमाण नीति (National Manufacturing Policy- NMP)** ने वनिरिमाण क्षेत्र में अवसंरचना, वनियमन एवं जनशक्ति में व्याप्त बाधाओं को उजागर किया। MII का लक्ष्य NMP के उद्देश्यों के आधार पर वनिरिमाण के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को 25% तक बढ़ाना और 100 मिलियन नौकरियाँ पैदा करना है, लेकिन स्थिति निराशाजनक बनी हुई है।





■ सहायक नीतियों को लेकर चर्चाएँ:

- जबकि MII मुख्य नीति है, 'मेड इन इंडिया' और 'मेक फॉर इंडिया' जैसी सहायक पहलें क्रमशः ब्रांडिंग एवं घरेलू वनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हालाँकि, ये पहलें MII की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के व्यापक लक्ष्य के लिये गौण ही हैं।

भारत में गहन औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये सुझाव:

■ आर्थिक विकास रणनीतियों पर पुनर्विचार करना:

- रघुराम राजन और रोहति लांबा ने 'बरेकगि द मोल्ड: रीडिमेजनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर' में एक अपरंपरागत दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा है। वे वनिर्माण-आधारित विकास से उच्च-कौशल, सेवा-संचालित विकास की ओर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं।
 - इसके साथ ही, इस दृष्टिकोण को वर्तमान औद्योगिक नीतियों के साथ तालमेल में होना चाहिये ताकि इसकी प्रभावशीलता का प्रभावी ढंग से दोहन किया जा सके।

■ गहन औद्योगीकरण के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण:

- भारत को अपने समाज को मौलिक रूप से बदलने के लिये गहन औद्योगीकरण की आवश्यकता है, न कि केवल सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की। इसमें व्यावसायिक कौशल और कारीगर ज्ञान के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ श्रम, उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी का पुनर्मूल्यांकन करना शामिल होगा।
- गहन औद्योगीकरण न केवल आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि जाति और वर्ग में नहित सामाजिक विभाजन को भी संबोधित करेगा।

■ श्रम-गहन क्षेत्रों पर बल देना:

- भविष्य की औद्योगिक नीतियों में गुणवत्तापूर्ण नौकरियों पैदा करने के लिये श्रम-गहन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना जारी रहना चाहिये। उच्च-स्तरीय वनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिये पारंपरिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।

■ नई औद्योगिक नीति (NIP '23) की भूमिका:

- NIP का मसौदा (जो फलिहाल रोक कर रखा गया है) उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को पूरकता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, दक्षता बढ़ाना और भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

(वर्षीष रूप से खलौने, परधन और जूते जैसे कषेत्रों में) ।

- इसे संबधति राज्य सरकारों की स्थानीय आधरति आकांक्षाओं और वनरिमाण वर्षीषजृजता का अनुसरण करते हुए शामिल एवं कार्यान्वति कथिा जाना चाहयि ।

■ समावेशी रोज़गार सृजन के लयि औद्योगकि नीतः

- भारत जैसे शरम-परचुर देश में, औद्योगकि नीतःको आम लोगों, वर्षीष रूप से महिलाओं के लयि रोज़गार सृजन को प्राथमकिता देनी चाहयि । उत्पादक रोज़गार सृजति करने और 'स्केल' हासलि करने के लयि शरम-गहन वनरिमाण महत्त्वपूरण है ।

■ नीतःनरिमाण में डेटा का महत्त्वः

- आरथकि नीतःनरिमाण के लयि डेटा व्याख्या और नैतिक दशिा-नरिदेश दोनों की आवश्यकता होती है । PLI के परभाव पर उच्च-आवृत्तः डेटा के अभाव में, नीतःनरिमाताओं को औद्योगकि नीतःको परभावी ढंग से आकार देने के लयि व्यापक सदिधतां पर भरोसा करना चाहयि ।

■ वकिास के लयि औद्योगकि नीतयिों का लाभ उठानाः

- रोज़गार सृजन और परतसिपरद्धात्मकता बढाने के लयि औद्योगकि नीतयिों (MII सहति) का लाभ उठाय़ा जाना चाहयि । हालाँकि चुनौतयिों मौजूद हैं, शरम-गहन वनरिमाण पर ध्यान केंद्रति करने से भारत को सतत वृद्धि और वकिास प्रापूत करने में मदद मलि सकती है ।

- MII भारत की आत्मनरिभरता की पछिली नीतयिों—जैसे 1970 के दशक के लाइसेंस राज और आयात-परतसिथापन औद्योगिकरण, से अलग है । जबकि संरक्षणवादी प्रवृत्तयिों के बारे में चतिाएँ मौजूद हैं, MII का लक्ष्य पछिली वफिलताओं को दोहराए बनिा घरेलू उद्योग को प्रोत्साहति करना है ।

- इलेक्ट्रॉनकिास वनरिमाण वस्तुओं के आयात में उच्च टैरफि बाधाओं जैसी संरक्षणवादी प्रवृत्तयिों ने इन नरिमाताओं को अपने आधार चीन, वयितनाम आर्द देशों में स्थानांतरति करने के लयि प्रेरति कथिा है । इस नीतःगित वसिगतिा नविरण कथिा जाना चाहयि ।

■ आरथकि वकिास में IR 4.0 को एकीकृत करनाः

- इसकी वर्षीषता यह है कि डिजिटलि, भौतिक एवं जैवकि दुनयिा के बीच की सीमाओं को धुंधला करने के लयि प्रौद्योगकिी का उपयोग कथिा जाता है और यह डेटा द्वारा संचालति होता है ।

- प्रमुख तकनीकों में क्लाउड कंप्यूटगि, **बगि डेटा**, स्वायत्त रोबोट, **साइबर सुरक्षा**, समिलेशन, एडटिवि मैन्युफैक्चरगि और **इंटरनेट ऑफ थगिस (IoT)** शामिल हैं ।

- **उदाहरणः जेनोबोट्स (Xenobots)**, जो एक मलिमीटर से भी कम लंबे होते हैं, 'फरस्ट लवगि रोबोट' के रूप में जाने जाते हैं । इन्हें 2020 में अफ्रीकी क्लॉ मैडक की स्टेम कोशकिाओं से बनाया गया था और इन्हें कृत्रमि बुद्धमितता का उपयोग करके प्रोग्राम कथिा जा सकता है ।

भारत में औद्योगकि कषेत्र के वकिास के लयि हाल की सरकारी पहलेंः

- [उत्पादन-आधरति प्रोत्साहन \(PLI\)](#)
- [पीएम गतिाशक्तिः राष्ट्रीय मासटर प्लान](#)
- [भारतमाला परयोजना](#)
- [सटारट-अप इंडयिा](#)
- [मेक इन इंडयिा 2.0](#)
- [आत्मनरिभर भारत अभयिान](#)
- [वनिविश योजनाएँ](#)
- [वर्षीष आरथकि कषेत्र](#)
- [एमएसएमई इनोवेटिवि योजना](#)

नषिःकरणः

- भारत के महामारी से अपेक्षाकृत जल्दी उबरने के बावजूद, इसे 'समय-पूर्व वःऔद्योगिकरण' और लगातार बनी रहती आरथकि असमानताओं जैसी चुनौतयिों का सामना करना पड़ रहा है । रघुराम राजन और रोहति लांबा ने वनरिमाण के बदले उच्च-कोशल, सेवा-संचालति वकिास पर ध्यान केंद्रति करने का प्रस्ताव कथिा है, जसिके बारे में उनका तर्क है कि इससे औद्योगिकरण को बढावा मलि सकता है । मूल कारण शकिा, नवाचार और शरम के परतसिासकृतकि दृषटकिेण में नहिति हैं, जो सुझाव देते हैं कि गहन औद्योगिकरण को प्रापूत करने और सामाजकि नीव को संबोधति करने के लयि व्यापक परविरतन की आवश्यकता है ।

अभ्यास प्रश्नः गहन औद्योगिकरण पर चर्चा करते हुए इसके महत्त्व, चुनौतयिों एवं आरथकि तथा सामाजकि वकिास पर इसके संभावति परभाव की चर्चा कीजयि ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

???????????????? ?????:

प्रश्नः 'आठ कोर उद्योग सूचकांक' में नमिनलखिति में से कसिको सर्वाधिक महत्त्व दथिा गया है?

- (a) कोयला उत्पादन
- (b) वदियुत उत्पादन
- (c) उरवरक उत्पादन
- (d) इस्पात उत्पादन

उत्तर: b

??????:

प्रश्न. "सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पछिड़ती गई है।" कारण बताइए। औद्योगिक नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)

प्रश्न. सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरति होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरति हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की वशाल संवृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बनिा एक विकसित देश बन सकता है? (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rethinking-india-s-economic-growth-model>

